श्री शिव चरण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल हिन्दी में पूछा है और उसका उत्तर किसी दूसरी भाषा में दिया गया है । मैं उसको समझा नहीं हूं ।

Accommodation for Central Government Employees

\+

*1113. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shrimati Tarkeshwari Sinha:
Shri S. C. Samanta:
Shri A. K. Kisku:
Shri S. N. Maiti:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri Yashpal Singh:
Shri Meetha Lal:
Shri Liladhar Kotoki:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Madhu Limaye:
Shri M. L. Sondhi:
Shri D. C. Sharma:

Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the number of Government employees who have not been allotted Government accommodation even after putting in more than 10 years continuous service;

(b) the reasons therefor;

(c) the steps taken to provide them with accommodation;

(d) the average waiting period for the employees for getting entitlement for the normal accommodation; and

(e) whether allotment on the basis of out-of-turn allotment are going to be re-opened again?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1021(i)/67].

(b) Due to shortage of residential accommodation in the general pool, it has not been possible to provide accommodation to a large number of Government employees.

(c) Due to financial stringency, it is not possible to undertake the construction of new residential units on a large scale. However, construction work on 3612 quarters is in progress and subject to the availability of funds, it is proposed to undertake the construction of another 3324 residential units during the year 1967-68.

The waiting period for getting entitled accommodation from the general pool varies from type to type and from city to city. A statement showing the dates of priority for different types of residences at various stations as on 30th June, 1967 is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1021(ii)/67].

(e) Out-of-turn allotments are covered under S.R. 317-B-9 of the Allotment Rules and are made in very deserving cases only.

श्री ओंकार लाल बेरवा : मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को दस साल से अधिक सर्विस करने के बाद भी दिल्ली में मकान उपलब्ध नहीं किया गया है, उन की संख्या 6919 है। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 55,000 के करीब है, जब कि मंत्री महोदय के अनुसार केवल 3612 क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इन 55,000 कर्मचारियों को जल्दी से जल्दी मकान उपलब्ध करने के लिए क्या योजना बनाई है और वेटिंग लिस्ट के अनुसार कौन सी प्रायर्टी डेट के सरकारी कर्मचारियों को मकान दिये जा चुके हैं।

श्री इकबाल सिंह : दस साल से ज्यादा सर्विस करने पर भी जिन गवर्नमेंट एम्पलाईज को अभी तक मकान नहीं मिले हैं उन के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया है । माननीय सदस्य ने पूछा है कि और कितने कर्मचारियों को मकान दिये जाने की योजना है । जैसा कि जवाब में बताया गया है, दिल्ली में और दिल्ली से बाहर लगभग 3600 नये मकान बन रहे हैं। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है कि दिल्ली में कितने सरकारी कर्मचारियों

को मकान नहीं मिले हैं, मैं उस के बारे में नोटिस मिलने पर पूरा नम्बर दे सकता हूं।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं ने क्या पूछा है और मंत्री महोदय क्या बता रहे हैं। मैं ने यह पूछा है कि वेटिंग लिस्ट के आधार पर कौन सी प्रायर्टी डेट कौन से बरस के कर्मचारियों को अभी तक मकान नहीं दिये गए हैं और मंत्री महोदय उल्टा सीधा जवाब दे रहे हैं।

श्री इकबाल सिंह : अलग अलग शहरों और अलग अलग टाइप्स के क्वार्टरों के एलाटमेंट के सम्बन्ध में जो पोजीशन है, वह एनेक्शर II में दी गई है।

Shri S. C. Samanta: The statement says that in Delhi, 6919 employees are not provided with Government accommodation. I would like to know what percentage of employees have been provided with accommodation and what is the provision in the fourth Five Year Plan for the Delhi State.

श्री इकबाल सिंह : परसेंटेज के आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। हम ने चौथी फ़ाइव-यीअर प्लान के लिए 54 करोड़ रुपये मांगे हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि हम को कितने मिल सकते हैं। हम को जो भी रकम मिलेगी, उस के मुताबिक मकान बनाने की कोशिश की जायेगी।

Shri A. K. Kisku: We have just now heard that owing to lack of funds, new houses for accommodation of Government employees could not be constructed. We know that house-rent is being collected from the Central Government employees. May I know what percentage of the amount is being spent on repairs and maintenance and what is being done about the balance of money that is accumulated year after year?

Shri Iqbal Singh: Repairs is quite a different subject. If the hon. Member gives notice, I can supply the figures.

Shri S. N. Maiti: Those Government employees who do not get accommodation are paid some house rent along with their salaries. May I know whether the amount paid to them is sufficient for them to get suitable houses and if not whether steps are being taken to give them sufficient house rent?

Shri Iqbal Singh: Headquarters allowance and house rent allowance are quite different. It is different and it is being given according to the availability of the accommodation.

श्री मधु लिमये : प्रश्न के अन्तिम हिस्से के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि इस तरह का एक नियम है, जिस के मातहत मंत्री लोगों को आउट-आफ़-टर्न एलाटमेंट के सम्बन्ध में विशेष या विवेकाधीन अधिकार मिल जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर गया है कि इस तरह के विवेकाधीन अधिकार देने के कारण उन का दुरुपयोग होता है और कई दफ़ा बड़े लोग इस बारे में मंत्रियों को चिट्ठियां लिखते हैं या टेलीफोन करते हैं। मंत्री महोदय "न" कर रहे हैं, लेकिन क्या उन को स्मरण नहीं है कि माननीय सदस्य, डा० राम मनोहर लोहिया ने पिछली लोक सभा के अध्यक्ष का एक पत्र सभा-पटल पर रखा था, जिस में उन्होंने कहा था कि मेरे क्षेत्र के एक निवासी को आउट-आफ़-टर्न एलाटमट कीजिए ? इस लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस नियम को ख़त्म करने के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं, जिस से बड़े लोगों के द्वारा इस आउट-आफ़-टर्न एलाटमेंट का दुरुपयोग न होने पाए।

श्री इकबाल सिंह : जहां तक आउट-आफ़-टर्न एलाटमेंट का ताल्लुक है, वह रूल्ज़ के मुताबिक की जाती है। माननीय सदस्य समझ सकते हैं कि दिल्ली में तकरीबन पचास हज़ार गवर्नमेंट एम्पलाईज़ हैं और उन सब को हम एकामोडेशन नहीं दे सकते हैं। उन

में से कितने ही आदमियों के केसिज जायज और डिजर्विन्ग हैं। अगर इस रूल को खत्म कर दिया गया, तो उन के साथ अन्याय होगा। एक तो मेडिकल ग्राउंड पर आउट-आफ़-टर्न एलाटमेंट को जाती है दूसरे, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट रिटायर हो जाय या उस की डैथ हो जाये, तो उस के बेटे को, अगर वह गवर्नमेंट एम्पलाई हो, आउट-आफ़-टर्न एलाटमेंट का जाती है। इस के अलावा मिनिस्टर्ज के पर्सनल स्टाफ़ को भी जो उन के नजदीक रहना चाहते हैं यह एलाटमेंट की जाती है। इस नियम के दुरुपयोग होने का सवाल नहीं है।

Shri M. L. Sondhi: I wish to say by way of preface to my question that the term "Government employees" is a legacy of the imperialist era. In a Welfare State, whether higher officer or lower officer, they should be partners in progress. May I know from the minister, when a new office is brought into being, does not the building of residential accommodation come about *pari passu* with the establishment of the office? Is there any policy decision in this respect?

Shri Iqbal Singh: There is no policy decision in this respect.

Shri D. C. Sharma: Sir, I am connected with a few autonomous corporations which build houses for their employees. There the allotment committee does not consist only of the bureaucracy but also of members from the public. May I ask the hon. Minister whether the allotment committee in his Ministry consists only of Secretaries, Deputy Secretaries, Assistant Secretaries and Under Secretaries or there are also Members of Parliament, both this House and also Rajya Sabha, who have also been associated with it?

Shri Iqbal Singh: This question relates to allotment of government accommodation to government employees. Allotment of houses by public undertakings is not covered by this.

श्री ओंकार लाल बेरवा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली राजधानी में कितने क्वार्टर्स ऐसे बने पड़े हैं जिनमें नल बिजली नहीं लगे हैं? वह कितने टाइम से बने पड़े हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के हैं?

श्री इकबाल सिंह : यह ठीक है कुछ क्वार्टर्स रामकृष्णपुरम् में हैं जो बिलकुल मुकम्मिल हैं लेकिन उन में अभी बिजली वगैरह नहीं लगी है। वह इसलिए नहीं लगी कि बिजली और पानी म्युनिसिपल कारपोरेशन से बहुत कहने के बावजूद भी वहां पर अभी तक नहीं आ सके। हम कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन बिजली और पानी आयेगा उसी दिन क्वार्टर्स एलाट करेंगे।

श्री ओंकार लाल बेरवा : कितने क्वार्टर्स हैं और कितने समय से पड़े हैं?

श्री इकबाल सिंह : काफी देर से हैं। कुछ क्वार्टर्स मेरे ख्याल से डेढ़ साल से पड़े हैं।

Shri Shradhakar Supakar: May I know if the Government keeps a record of the officers who retire without taking any accommodation at all throughout their life? Secondly, may I know how far it is possible for the Government to give notice to the employees that beyond a certain period they will not be entitled to any accomodation at all so that they may not wait and wait for ever?

Shri Iqbal Singh: Regarding allotment of accommodation to government servants I have given the dates for different cities. Where the government servants have been waiting for a long period, say more than 20 years, we try to build more houses. In Bombay, for example, we are constructing more houses, so that the length of time for which the government servants have been waiting without accommodation may be reduced.

Mr. Speaker: The question was whether the Government keeps any record of the government servants

who retire without getting any accommodation at all.

Shri Iqbal Singh: I have no information at present. If the hon. Member gives notice I can collect the information.

Rajasthan Canal

+

*1114. **Shri Ram Kishan Gupta:**
Dr. Karni Singh:
Shrimati Nirlep Kaur:
Shri N. S. Sharma:
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Sharda Nand:
Shri Brij Bhushan Lal:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the work on the Rajasthan canal is not progressing according to schedule;

(b) if so, the reasons thereof; and

(c) the proposals made by him following his recent visit to Jaipur to speed up the work of the Rajasthan Canal?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao): (a) to (c). The first stage of the Rajasthan Canal Project is to be completed in the year 1970-71. So far, the progress has been generally in accordance with this programme. In order to adhere to the schedule, the question of providing adequate funds for the project is under consideration.

Shri Ram Kishan Gupta: May I know how much amount has been spent so far and how much more will be required?

Dr. K. L. Rao: The expenditure up to March, 1967 is Rs. 47 crores and another Rs. 28 crores is required to complete the canal (first phase).

Shri Ram Kishan Gupta: What is the agency through which the work is executed?

Dr. K. L. Rao: Through different contractors and also departmentally (*Interruption*).

Mr. Speaker: We have covered only two questions so far in 35 minutes. It is not as though we are going very fast. The first question was not answered because the PAC Chairman objected. We have covered only the second and third questions.

Shri Piloo Mody: Let us go faster.

Shri Hem Barua: It is not the number of questions that we cover but the information that we get which is important.

Mr. Speaker: Unfortunately, I have to call all the names of Members who have tabled the question. There is no question of one being an important Member or anything like that.

श्री शिवनारायण : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है। यह जो क्वेश्चन अवर है उस में एक नाम पहला आप बुला लीजिए उस के बाद जो मेम्बर हाउस में खड़े हों उन में से आप बुलाइए।

Mr. Speaker: Your suggestion is very valuable.

Shri Vasudevan Nair: He never takes the pain of asking a question.

श्री आरबानन्द : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना के बनाते समय इस पर कितना रुपया खर्च करने का अनुमान था और आज वह अनुमान दुगुना और तिगुना हो गया है? क्या यह कारण नहीं है कि जिस से इस योजना की प्रगति नहीं हो रही है?

Dr. K. L. Rao: The present estimate for the first stage of the Rajasthan Canal is Rs. 75 crores and we are able to work close to this estimate. Rs. 47 crores have been spent so far. The progress of the project is not affected on account of any increase in estimate in this case.